Survey of under ground water resources in Rajasthan

1604. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state;

(a) whether Government have conducted a detailed survey of underground water resources in Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) Yes, Sir.

(b) Based on the results of Hydrogeological surveys and scientific exploration, the Ground Water resources of Rajasthan have been estimated at 16.224 cubic kilometers.

Vacating of villages in Narmada valley

1605. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat and Maharashtra Governments have ordered the tribal villagers in the Narmada Valley to vacate their villages in January, 1992 since those villages are under submergence because of the construction of the dam there;

(b) whether it is also a fact that the tribals living in that area have objected to the vacation from their villages and the agitation is going on; and

(c) what measures Government have taken for settling the dispute by amicable means?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The Governments of Gujarat and Maharashtra have issued notices in January 1992 to the tribal villagers who are likely to be affected by temporary submergence during 1992 monsoon due to pondage as well as natural flood estimated on "one in hundred years flood" and its back water effects due to construction of the dam. As per the provision of Narmada Water Dispute Tribunal Award, the oustee families must vacate the submergence area at least six months before the onset of submergence season.

(b) While the trivals living in the area of Gujarat are not objecting to the vacation from their villages, villagers from Manibeli village in Maharashtra havo objected to the vacation from the village and agitation is going on.

(c) Government of Maharashtra have further liberalised the rehabilitation policy in February 1992 by which all the major sons and daughters will get agricultural land, house plots and other monetary benefits. Publicity compaign has also been started in the submergence villages to inform the Project Affected Persons (PAPs) abut the Rehabilitation and Resettlement packages vis-a vis the benefits that would accrue from the project when completed non Government Voluntary Organisation (NGVOs) have also been actively engaged in the Rehabilitation & Resettlement work of the project. The Government of Maharashtra is also trying to start dialogue with the villagers of Manibeli who have not shifted so far.

Linking of rivers in the country

1606. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether linking of Southern rivers namely Mahanadi—Godavari—Krishna—Cauveri has been considered afresh: and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b) The National Water Development Agency has taken up the study of the national perspective plan for water resources development formulated in 1980. The study under peninsular development component *inter-alia* envisages inter-linking of Mahanadi—Godavari—Krishna—Pennar—Cauvery and Vaigai rivers. It has so far prepared preliminary feasibility reports of nine links, four of which form part of the Mahanadi—Godavari — Krishna—Pennar—Cauvery—Vaigai

link. There is no new proposal under consideration.

वर्षा जल का उपयोग

1607. **श्री राम नरेश यादव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा जल के उपयोग हेतु कोई योजना तैयार की है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी कितनी योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश में 4000 घन किलोमीटर वार्षिक वृष्टि होती है, जिसमें से नदियों में उपलब्ध औसत वार्षिक प्रवाह लगभग 1850 क्यूबिक किलोमीटर है । स्थलाकृतिक जल-वैज्ञानिक और अन्य बाधाओं के कारण, वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों के अतिरिक्त, जो लगभग 450 क्यूबिक किलोमीटर है, उपयोज्य सतही जल का मूल्यांकन 690 क्यूबिक किलोमीटर किया गया है । राज्य सरकारें उपयोज्य जल का उपयोग बढ़ाने के लिए वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही हैं । उपयोज्य जल के उपयोग में वृद्धि करने के लिए कुओं से सिंचाई और लघु सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त अब तक पूरे देश में कुल 263 वृहद सिंचाई परियोजनाएं 1104 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं प्रारंभ की गई है । अब तक 83 वृहद परियोजनाएं और 777 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गयी हैं । इस समय कुल 1140 क्यूबिक किलोमीटर उपयोग मात्रा में से 552 क्यूबिक किलोमीटर जल के उपयोग का निर्धारण किया गया है ।

उपयोज्य जल की उपलब्धता को अधिकतम बढ़ाने के लिए सरकार से अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है, जिसमें दो घटक अर्थात् हिमालयाई नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक सम्मिलित किए गए हैं । राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण, प्रत्येक घटक में वृहद्ध नदियों का अन्त सम्पर्क करने पर विस्तृत अध्ययन करने में लगा हुआ है । प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में 17 जल अन्तरण सम्पर्कों में से जल अन्तरण सम्पर्कों पर अध्ययन पहले ही पूर्ण किए गए हैं और प्रारम्भिक व्यवहार्यता रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को सहमति हेतु भेजी गयी हैं । शेष जल अन्तरण सम्पर्कों के लिए अध्ययन आठवीं योजना में पूर्ण किए जाने का कार्यक्रम है । हिमालयायी घटक पर भी अध्ययन हाल ही में प्रारम्भ किए गए हैं । जहां वर्षा होती है वहां उसका जल संरक्षित करने एवं उसका उपयोग करने के लिए जल विभाजक विकास कार्यक्रम अलग से प्रारम्भ किए गए हैं । किन्तु वाष्पीकरण और वनस्पति हानियों और नदी भूभाग का अनुरक्षण करने के लिए नदी में जल की कुछ मात्रा प्रवाहित करने की आवश्यकता के कारण वर्ष जल का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं है ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

1608. **श्री रणजीत सिंह** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्माणाधीन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समस्त कार्य सन 2004 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के पूरा होने में अनपेक्षित विलम्ब होने के कारण पिछले वर्षों में इसकी निर्माण लागत बढ़ गयी है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कुल कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हो चुकी है;